राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25: एक विश्लेषण

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र, जयपुर
Budget Analysis and Research Centre
(www.barctrust.org)

राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 : एक विश्लेषण

उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने वर्तमान भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा । इसके अलावा 9 अन्य संकल्पों, जिसमें बुनियादि सुविधाएं पानी बिजली- सड़क, सुनियोजित शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय, विकास, किसान का आर्थिक सशक्तिकरण सतत् एवं हरित विकास, मानव संसाधन विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आदि शामिल हैं, के साथ वर्ष 2024 25 का परिवर्तित बजट पेश किया।

बजट भाषण में सरकार ने बताया कि वर्तमान में अर्थव्यस्था का आकार 17.81 लाख करोड़ रूपए है, जो लगभग 213 बिलियन डॉलर है। इसे अगले 5 सालों में 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिये अर्थव्यस्था की वृद्धि दर चालू कीमतों पर लगभग 13 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिये । आर्थिक समीक्षा 2023 24 के अनुसार राज्य में आर्थिक वृद्धि की दर कोरोना के बाद से ही 12 प्रतिशत से अधिक ही रही है । इस प्रकार यह कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है ।

इससे पहले राज्य सरकार ने फरवरी में राज्य का अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें कुछ घोषणाएं की गई थीं । परिर्वतित बजट में राज्य सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया। पंचायत एवं शहरी निकायों के साथ सहकारी समितियों के चुनाव भी साथ-साथ करवाने की घोषणा की तथा खाटू श्याम जी में वाराणासी में बने कॉरीडोर की तर्ज पर कॉरीडोर बनाने की भी घोषणा की गई तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पद्वी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है |

राज्य आर्थिक स्थिति

बजट के साथ जारी किये गये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर 2021 22, 2022-23 एवं 2023 24 में क्रमशः 8.95 प्रतिशत, 7.81

प्रतिशत तथा 8.03 प्रतिशत रही है, तथा वर्ष 2023 – 24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर दरों पर 90,831 रूपए है |

सारणी 1 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर (प्रतिशत)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	**5.45**	-1.82	8.95	7.81	8.03
प्रचलित मूल्यों पर	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56

स्रोत : राजस्थान आर्थिक समिक्षा 2023 24

कृषि, जिस पर देश की अधिकांश जनता निर्भर है, की वृद्धि दर घटकर वर्ष 2023-24 में 2.13 प्रतिशत रह गई, वहीं औद्यौगिक वृद्धि की दर 12.43 प्रतिशत रही है, जो कोरोना के बाद सर्वाधिक है। सेवा क्षेत्रों में भी 2023-24 में आर्थिक वृद्धि की दर में वर्ष 2021-22 में 14.51 प्रतिशत थी जो कम होकर 2023-23 में 9.85 प्रतिशत तथा 2023-24 में 6.37 प्रतिशत तक आ गई। इसके साथ ही राज्य में बेरोज़गारी एवं मंहगाई जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इस बजट से राज्य के सभी वर्गों के लिये घोषणाएं करने का प्रयास किया है ।

सारणी 2 : स्थिर (2011 - 12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)	1.77	5.71	-2.12	9.45	7.35	6.92
कृषि क्षेत्र	5.33	12.27	6.30	2.50	4.56	2.13
उद्योग क्षेत्र	-13.49	4.43	2.68	9.47	6.31	12.43
सेवा क्षेत्र	11.39	2.78	-10.22	14.51	9.85	6.37

स्रोत : राजस्थान आर्थिक समिक्षा 2023-24

वित्तीय स्थिति

इस वर्ष बजट का आकार 4.95 लाख करोड़ का है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 26.76 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार बजट के आकार में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

सरकार की राजस्व प्राप्तियां भी पिछले वर्ष के 2.34 लाख करोड़ रूपए (बजट अनुमान) से बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रूपए हो गई हैं। उसी प्रकार सरकार का राजस्व व्यय 2.58 लाख करोड़ रूपए (बजट अनुमान) से बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रूपए हो गया है। हालांकि राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 40 प्रतिशत) वेतन एवं पेंशन पर खर्च होता है ।

इस तरह सरकार का राजस्व घाटा 25,758 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत है। वहीं, 2024 25 में 44216 करोड़ रूपए का पूंजीगत खर्च अनुमानित है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 6 हज़ार करोड़ रूपए अधिक है। सरकार का **राजकोषीय घाटा,** जो लगभग इस साल में लिये गये ऋण के बराबर होता है, 70 हज़ार करोड़ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.93 प्रतिशत है।

बजट घोषणाएं

इस बजट में कई प्रमुख घोषणाएं भी हुई हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना में कैंसर रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए और राहत देने की घोषणा की गई है। लेकिन इस योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी के अलावा अन्य रोगी ले सकेंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। उसी प्रकार इस वर्ष 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है वित्त मंत्री महोदया ने राज्य में आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन की घोषणा की है, जिसमें आगामी 3 वर्षों में 15 हज़ार करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे। बच्चों के पोषण की दिशा में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सप्ताह में 3 दिन दुध दिये जाने की घोषणा हुई है। हांलाकि कई राज्यों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अण्डा भी उपलब्ध करवाया जाता है । कृषि क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण नीति लाये जाने तथा श्री अन्न प्रोत्साहन एजेसीं की घोषणा भी की गई है ।

इस बजट में राज्य सरकार ने शहरों में जन सुविधाएं बढ़ाने के लिये बहुत सारे छोटे छोटे कार्य जैसे- छोटी सड़कें, नाले, पानी की निकासी आदि कार्यों की घोषणा की गई है, जो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप की तरह भी देखा जा सकता है।

इस बजट में उद्योग व्यापार को भी विभिन्न प्रकार की एमनेस्टी के माध्यम से लाभ पहुंचाने की घोषणाएं हुई हैं। उपमुख्यमंत्री ने उद्योगों एवं व्यापारों को लगभग 7 प्रकार के विभिन्न करों के बकाये कर भुगतान पर 10 लाख रूपये तक की छुट तथा कई मामलों में 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक छुट की घोषणा की है ।

भिन्न क्षेत्रों (sectors) का बजट

अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य में राजस्व बजट कुल राजस्व व्यय का 8 प्रतिशत है परन्तु स्वास्थ्य में कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) कुल बजट का मात्र 5.5 प्रतिशत ही है । स्वास्थ्य बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले खासी बढ़ोत्तरी हुई । शिक्षा में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 9 प्रतिशत अधिक आंवटन हुआ है। वहीं कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों का बजट लगभग पिछले वर्ष के संशोधित बजट से 6 प्रतिशत बढ़ा है। हांलाकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के बजट में पिछले वर्ष के संशोधित बजट से 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास का बजट पिछले वर्ष के बजट अनुमान के सामान ही है, जबकि संशोधित अनुमान से 15.6 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 3 : क्षेत्रवार बजट (करोड़ रूपए)

क्षेत्र		**2023-24 बजट अनुमान**	**2023-24 संशोधित अनुमान**	**2024-25 परिवर्तित बजट अनुमान**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	18,038.27	20,284.85	23,479.19
	पूंजीगत	4,026.1533	3,687.8768	4,180.98
	कुल	**2,2064.42**	**23,972.72**	**27,660.18**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	राजस्व	56052.03	5,6525.57	62,516.14
	पूंजीगत	1,900.87	3,067.76	2,556.58
	कुल	**57,952.90**	**59,593.33**	**65,072.72**
जल एवं स्वच्छता	राजस्व	4,488.27	4,668.5349	5,196.3437
	पूंजीगत	5,284.9895	4,553.7113	6,073.7075

	कुल	**9,773.2595**	**9,222.2462**	**11,270.0512**
शहरी विकास	राजस्व	7,790.26	9,199.5183	10,629.9035
	पूंजीगत	6,249.8151	3,635.1243	6,288.1905
	कुल	**14,040.0751**	**12,834.6426**	**16,918.094**
पोषण	राजस्व	3,046.6062	3,117.7102	3,654.7571
	पूंजीगत	17.0007	35.3973	30.0344
	कुल	**3,063.6069**	**3,153.1075**	**3,684.7915**
अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	राजस्व	2,334.47	2,206.39	2,676.71
	पूंजीगत	766.87	751.95	829.60
	कुल	**3,101.34**	**2,958.34**	**3,506.31**
उर्जा (बिजली)	राजस्व	23,512.80	29,520.36	28,054.52
	पूंजीगत	1,610.76	901.00	1,576.80
	कुल	**25,123.56**	**30,421.36**	**2,9631.33**
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	राजस्व	11,930.97	12,647.57	13,742.26
	पूंजीगत	932.65	1,031.32	802.22
	कुल	**12,863.62**	**13,678.89**	**14,544.48**
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	राजस्व	2,483.22	2,498.82	2,871.49
	पूंजीगत	6,285.54	5,889.11	6,934.67
	कुल	**8,768.76**	**8,387.93**	**9,806.16**
ग्रामीण विकास	राजस्व	19,418.30	16,612.28	19,479.74
	पूंजीगत	1,000.11	1,113.03	1,014.03
	कुल	**20,418.40**	**17,725.31**	**20,493.77**

स्रोत : राजस्थान बजट 2024-25

शिक्षा, युवा एवं रोजगार

युवाओं के लिए राज्य कौशल नीति, 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, अटल एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ तक फंडिंग, स्टार्टअप्स को विभागों से काम मिलने में आसानी, अगले दो वर्षों में 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने, तीन इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में उन्नयन, छात्रावासों को मैस भत्ता ढाई हजार रुपए दिमाग से बढ़कर 3,000 रूपये तथा खेलकूद आवासीय विद्यालयों के छात्रों का मेस भत्ता 4,000 रूपये किया गया है ।

शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत एवं ज्योतिषी शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए घोषणाएं हुई हैं। साथ ही, **खेलों** को प्रोत्साहन पर काफी जोर दिया गया है। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा हुई है, जिस पर 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये व्यय होंगे । तथा संभागीय स्तर भी खेलकूद महाविद्यालयों की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपये की राशि से की जानी प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बजट

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति विकास निधि की राशि एक एक हज़ार करोड़ रुपये से बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये हुआ है। **बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना** के तहत 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा आंतरिक सड़कें, पेयजल, ठोस कचरा प्रबंधन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 (पचहत्तर) करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ **गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना** शुरू किये जाने की घोषणा करती हूँ । इसके अन्तर्गत आदिवासियों के जल जंगल -

जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्रा में सामुदायिक पट्टे सामुदायिक वन अधिकार दिए जाकर सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, agro-forestry, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण मद के बजट 3,506 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत बढ़ा हुआ है ।

सामाजिक सुरक्षा के उपाय

फेरी वालों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लाभार्थियों को 25,000 रूपये अतिरिक्त अनुदान, विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री घुमंतू आवासीय योजना तथा पाक विस्थापितों को आवास हेतु 1 लाख रूपये प्रति परिवार की सहायता की घोषणा की गई है । ईडब्ल्यूएस के युवाओं, बालिकाओं एवं परिवारों के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान भी किया गया है ।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए 15 लाख लखपति दीदी तथा आंगनबाड़ी में दूध के अलावा 5 वर्षों में 2 लाख नए एवं सहायता समूह का गठन कर उनके लिए 300 करोड़ रुपये की ऋण की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं हॉस्टल के लिए 35 करोड रुपए और बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल भी प्रस्तावित हैं । भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में पं.मा.व. योजना की राशि को पांच हज़ार से बढ़ा कर आठ हज़ार करने का वादा किया गया है । अतंरिम बजट में इसे बढ़ाकर 6,500 रूपए की घोषणा की जा चुकी है ।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि, रेयर डिजीज के लिए फंड, दिव्यांग जनों के लिए जामडोली परिसर में स्वयंसिद्धा सेंटर फ्लोर एक्सीलेंस केंद्र की भी घोषणा हुई है। **गिग वर्कर्स** के लिए ई-कॉर्मस तथा ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाली **कंपनीयों से सामाजिक सुरक्षा शुल्क** लेकर 250 करोड़ रुपये की निधि का गठन किया जाना प्रस्तावित है |

पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास पर ज़ोर

इस बजट में सबसे सराहनीय बात रही पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास पर ज़ोर । वित्त मंत्री ने ग्रीन डेवलेपमेंट पर जोर देते हुए 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ससलेनबलीटी आधारित औद्योगिक नीति लाये जाने, विद्युत परिवहन को बढ़ावा, सी एन जी एवं पी एन जी पर वैट में कमी जैसी घोषणाएं की हैं, जो पर्यावरण संरक्षण एवं मौसम के अनुकुल विकास की दिशा में उठाए गये कदम हैं। साथ ही सरकार ने राज्य में 20 हज़ार हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, मिशन 'हरियालो राजस्थान' की घोषणा की है तथा अगले वर्ष से ग्रीन बजट लाए जाने का वादा भी किया है। हालांकि यहां वन संरक्षण करते हुए वनों पर आश्रित समुदायों के हितों का ध्यान रखना भी आवश्यक है ।

कुल मिलाकर राज्य सरकार ने इस बजट से राज्य के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है और कई अच्छी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में मात्र 8 माह ही बाकी हैं और सरकार के पास समय की कमी है ऐसे में बजट को अमलीजामा पहनाना एक चुनौती साबित होगा।